भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 871
जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी

871. श्री आनन्द शर्मा :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में तेजी से गिरावट के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूरे देश में उत्पादन में गिरावट, फैक्टरियों के बंद होने और आर्थिक मंदी के कारण काफी बड़ी संख्या में फैक्टरी कामगरों, तकनीशियनों और प्रबंधकों ने अपना रोजगार खो दिया है;

(घ) यदि हां, तो ऑटो सेक्टर में अनुमानित तौर पर कितने लोगों ने नौकरियां और रोजगार खो दिया है; और

(ङ) सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए किन-किन हस्तक्षेपों को करने का विचार रखती है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): अनेक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 14.1 मिलियन वाहनों की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2019 के दौरान 11.7 मिलियन वाहनों (सभी श्रेणी) की बिक्री हुई। लेकिन त्यौहारी मांग से यात्री वाहन सेगमेंट में 0.3% की दर से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। उद्योग द्वारा अस्थाई कार्यबल की छटनी की सूचना दी गई है। तथापि, सरकार के पास रोजगार खोने के कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) जब कभी आवश्यक होता है, सरकार एक नीति निर्माता के रूप में हमेशा ऑटो सेक्टर के व्यापक और सतत विकास के लिए अनेक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने एवं इसमें सुधार करने का प्रयास करती है। ऑटोमोटिव में मंदी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- कारपोरेट कर को 22% तक कम करना
- भविष्य में आईसीई और ईवी का पंजीकरण जारी रखना
- स्क्रैपेज नीति पर विचार किया जा रहा है
- नई कारों के पंजीकरण में प्रस्तावित वृद्धि को जून, 2020 तक आस्थगित कर दिया गया
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹70,000 करोड़ की निधि जारी की गई
- खरीदे गए वाहन पर लिए जाने वाले ब्याज को रेपो रेट से जोड़ना

******